1991. the next revision can be effected only on or after 01.08.1994. Government have constituted a Study Group to consider the case for revision in rates of royalty. The concerned of Governments have already placed their points of view before the said Study Group.

कोल इंडिया लि० द्वारा परियोजनाओं का विकास किये जाने हेतु स्वीकृति

6260. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत खानों से संबंधित 167 परियोजनाओं के विकास हेतु कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गई थी और इन परियोजनाओं के विकास हेतु अनुमानत: कितनी धनराशि अपेक्षित थी और क्या यह धनराशि भी आवंटित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं का विकास कार्य मार्च, 1994 तक भी आरम्भ नहीं हुआ था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है जिनमें उत्पादन शुरू हो गया है, जो निर्माणाधीन हैं और जिनमें विकास कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है और सभी परियोजनाओं में किस तारीख तक उत्पादन आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) 2 करोड़ रु० अथवा इससे अधिक लागत की 166 भूमिगत परियोजनायें राष्ट्रीयकरण के बाद तथा 31-3-1994 तक कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों में 3631.89 करोड़ रु० के कुल स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय सहित कार्यान्वयन के लिये अनुमोदित हुई है।

इन परियोजनाओं पर निधियों का नियतन कार्यान्वयन की स्थिति तथा संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुये वार्षिक योजना प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। दिसम्बर, 1993 तक इन परियोजनाओं पर संचयी व्यय 2286.10 करोड़ रु० की राशि का था।

(घ) और (ङ) इन सभी परियोजनाओं में विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 140 परियोजनाओं में कोयला उत्पादन पहले ही आरम्भ हो गया है। शेष 26 परियोजनाओं में से 16 में आठवीं योजनावधि की शेष अवधि में कोयले का उत्पादन होने की संभावना है तथा 10 में 9वीं योजना अवधि के दौरान उत्पादन होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी

6261. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कोयले की भारी कमी ; है

(ख) यदि हां, तो इस राज्य को कोयले की कितनी मात्रा आवंटित की गई है और राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को इसका कितने प्रतिशत कोयला आवंटित किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार इस राज्य को और अधिक मात्रा में कोयला आवंटित करने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जा रहा है । उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 में कोल इंडिया लि० (को०ई०लि०) से उत्तर प्रदेश को आपूर्ति किये गये कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है:—

(000 टन में)

वर्ष	कुल आपूर्ति (आंकड़े अनंतिम) (कोलियरी उपभोग को छोड़कर)
1990–91	27641
1991–92	30487
1992–93	33719

इस संबंध में विद्यमान सूचना प्रणाली के अनुसार राज्य के जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये गये कोयले के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कोयला कम्पनियों को कोयले आपूर्ति में वृद्धि किये जाने की सलाह दी गई है । कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इस संबंध में कोयले के उत्पादन में नई खानों को खोलकर तथा विद्यमान खानों का पुनर्गठन करके कोयले के उत्पादन में वृद्धि किये जाने लिये कदम उठाये गये हैं ताकि उत्पादन के अधिकतम स्तर को प्राप्त किया जा सके ।

इसके अलावा सरकार ने विद्युत उत्पादन किये जाने के लिये तथा अन्य विशिष्ट अंतिम प्रयोगों के लिये ग्रहीत उपभोग के प्रयोजन से संभावित क्षेत्रों में कोयला खनन क्रियाकलापों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया है । उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत कुछ विनिर्दिष्ट खानों से जिनके पास बड़ी मात्रा में स्टाक है और वे बिना किसी तरह के प्रयोजन पर जोर दिये, कोयले की आपूर्ति कर सकती है । बढ़ी हुई मात्रा में कोयले को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

Coal gassification project initiated in collaboration with CSIR

6262. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the latest stage of the implementation of the coal gassification project being initiated in collaboration with CSIR as on 1-4-94;

(b) what is tne provision of funds of the project; and

(c) when the project is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (c) A 45 Megawatt (MW) capacity demonstration plant (30 MW to be generated through gas turbine and 15 MW through steam turbine) for generation of power through Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) system is proposed to be implemented with the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) as the nodal agency. A project document for implementation of coal gasification project has been prepared by CSIR.

The estimated cost of the IGCC demonstration plant as a profit is Rs. 240 crores and an amount of Rs. 3 crores